

tific institution, he actually employed a team of scientists; and instead of the team of scientists going to the institutions, which they were supposed to cater, he is right that they were located in Delhi and we don't know what scientific work was going on there. Therefore, when we enquire into the matter we will take all these aspects into account, including the one which the hon. Member has made a reference to.*

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : The hon. Finance Minister is considering the assets created by Brahmchari. I would invite his attention to the fact that in the State of J & K in Udhampur, the Brahmchari has occupied forest land measuring over 200 kanals and State land measuring over 150 kanals, on which he has built properties worth crores of rupees. I would like to know for the purchase of all this property, from where that money came. I would also like to know whether that income was at all assessed and what is the source thereof? That should be inquired into.

PROF. MADHU DANDAVATE : I think I have given a general assurance that we will inquire in depth into all the financial assets of Brahmchari.

MR. CHAIRMAN : Now, he assures you.

Recommendation of the Falta Export processing zone advisory committee on export processing zones

*203. SHRI SHIV PRATAP MISHRA :
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Falta Export Processing Zone Advisory Committee:

The question "was actually asked on the floor of the House, by Shri Shiv Pratap Mishra.

tee had, at its first meeting held on July 3, 1990, urged the Central Government to bring about some policy modifications so as to extend more incentives for Export Processing Zones ; and

«' (b) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU) : (a) and (b) Two meetings of the Advisory Committee set up for the Falta Export Processing Zone have been held, one on July 13, 1990 and another on August 4, 1990. Formal proposals from the Development Commissioner on the recommendations of the Committee are awaited.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: To boost up the country's exports and earn more foreign exchange, what are the detailed incentives recommended by Export Processing Zone Committee and what action has been taken thereof?

SHRI ARUN KUMAR NEHRU : As I mentioned earlier, its meetings were held on 13th of July and on 4th of August. Only on 20th of August we have received the recommendations. We have asked the Development Commissioner to give his comments. I say so because it is after we receive the comments of the Development Commissioner, that we will have a meeting of the Committee of Secretaries, which involves many Ministries. Then the Commerce Ministry will take a view. I have, however, got a copy of their report. I can also give answer as to what we are planning to do. But I think it would be a little premature to do that. So, we should wait for the comments of the Development Commissioner, because that is the procedure. •

' SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

May I know from the Minister whether the Government proposes to set up more export processing

zones in the country ? If so, what are the details thereof ?

SHRI ARUN KUMAR NEHRU : Sir, there are already six export zones and if we analyse over the last three or four years, they have done reasonably well. Our turnover has gone up from nearly Rs. 320 crores in 1985, we estimate, to about Rs. 1000 crores. We have also approached the State Governments if we get any proposals for setting up of additional zones; we will consider them favourably. But at the present moment, we have got FALTA and we are also examining Vizag but if we have valid proposals from the States we will consider them favourably.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 13 जुलाई और 4 अगस्त की कैबिनेट निर्णयित संसदन क्षेत्र के त्रिदेव स्थापित सलाहकार समिति की जो बैठक हुई, उसमें, सिफारिशों पर इनके विकास आयुक्तों से अब तक पूर्ण रूप से विवरण आ जायेगा और कब तक इस मामले का वे कानून के रूप में लागू करेंगे ?

इससे बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि कैबिनेट एक्सपोर्ट जोन पिछले दो तीन साल में किसी प्रगति कर चुका है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और पिछले तीन सालों में इसने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितनी मशीनरी आया मेटेरीयल का इंपोर्ट किया गया है।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्यों एक्सपोर्ट इंटेलिजेंड बन्द किया गया है क्योंकि जब तक हम इंटेलिजेंड नहीं देंगे तब तक विदेशों में हमारा निर्यात पूर्ण रूप से नहीं हो पायेगा और जो इंटेलिजेंड इस सरकार ने रोक दिया है उसको एक न एक दिन चालू करना होगा, बिना इसके एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ नहीं सकती ?...

श्री सभापति : आप इंटेलिजेंड की बात करिये, बहुत लम्बा सवाल मत काजिये... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूँ कि अम. भारत के भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री, देवलाल जी, ने आरोप लगाया हमारे माननीय मंत्री जी पर कि उन्होंने कमीशन लिया है। हो सकता है की यह झूठ हो, लेकिन...

श्री सभापति : फॅल्टा में ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंड इंग्लिश में क्या कोई कमीशन की बात चल रही है, इसलिये डिले किया जा रहा है और एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है ? मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मंत्री जो कमीशनखोर नहीं हैं। तो क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस कमीशन के नाम पर इन्फाल्व तो नहीं हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: That should be expunged, It should not go on record.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman, Sir, you cannot per mit it.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, न मैंने कोई असंशय बात कही है, न कोई असत्य कहा है, न कोई अतथ्य कहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कमीशनखोर हमारे मंत्री नहीं हैं। लेकिन इस तरह का आरोप भारत के भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने लगाया है। तो और लोग तो नहीं खा रहे हैं, कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह तो नहीं हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अरुण नेहरू : सभापति महोदय, पहली चीज तो यह है कि जो कुछ सुझाव आये हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो उसके बाद ही उन पर कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा चीज फैला में जो एक्सपोर्ट ज़ोन है, 1984-85 में वहाँ पर वह स्थापित किया गया था और आँकड़े जा हैं उनके अनुसार पहले साल में 2 कराड़ का एक्सपोर्ट हुआ था और पिछले तीन सालों का परफॉर्मंस देखिये तो 8 कराड़ का, 16 कराड़ का और इस साल के सारा महीनों में साढ़े तेरह कराड़ का एक्सपोर्ट किया गया है। ताइपेड इसमें अच्छा है। दूसरा चीज आने जहाँ है कि इन्वेस्टिव विद्वान किये गये हैं। कोई इन्वेस्टिव विद्वान नहीं किया गया है। ए० सजेशन यह आया है कि फैला में इन्वेस्टिव और देने चाहिये। मगर जो भी हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उसमें कोई इन्वेस्टिव विद्वान नहीं किया गया है। मगर एक समस्या सबके सामने आ रही है कि एक्सपोर्ट ज़ोन में थोड़े से इन्वेस्टिव सरकार ने जो दिये हैं और जो डामेस्टिक ट्रेफिक एरिया होता है उसमें भी ... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : बनारस में गलीचों का एक्सपोर्ट होता है। उसमें इन्वेस्टिव कोई नहीं मिल रहा है।

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: The hon. Member should understand the subject. You can either talk about Falta and 100 per cent export zone or you can talk about domestic area at Va-ransi and other exports. He has to get his priority right. I can assure you that there is no phosphoric acid in Falta. You know it is a couple of thousand miles away. But I would suggest that if he does his homework and ask whatever he wants, we are willing to answer.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : वह भी जवाब दे दिया है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : नहीं दिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, मंत्र। महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि फैला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के निर्माण के समय जो परिकल्पना की गई थी कि वह परिकल्पना अभी तक 10 परसेंट भी पूरी नहीं की गई है। और उसे सिर्फ निजा पूंजी के इन्वेस्टिव के आधार पर छाड़ दिया गया है इसलिये क्या सरकार ऐसी वस्तुओं की निर्यात की संभावना है, अपनी तरफ से कोई पहल कदमी बनाने की योजना बना रहा है या नहीं बना रहा है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : पहली चीज तो यह है कि फैला के बारे में जो आँकड़े दिये गये हैं उसमें आपने देखा होगा कि पिछले तीन सालों में एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है। मगर जो भी कोई हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ज़ोन होता है उसमें कोई पब्लिक सेक्टर द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने यूनिट्स नहीं लगते हैं। वहाँ प्राइवेट सेक्टर को ही एनकुरेज करना पड़ता है। यह जो दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आई है उसमें इन्वेस्टिव के विषय में काफी कहा गया है और दूसरी चीज यह भी कहा गई है कि जो प्रदेश सरकारें हैं उनको बर्ग काफ़ी काम करना है। इस वक़्त केन्द्रिय सरकार की तरफ से 16 करोड़ रुपये वहाँ खर्च किये जा चुके हैं।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Chairman, Sir, I have had an opportunity to look into the working of this export promotion zone, particularly Falta. I personally visited a couple of years back. The concept of export promotion zone is valuable. I am not really in agreement with the hon. Minister when he is giving a very encouraging picture. I presume, maybe things are moving ahead.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Unless I say some background things...

MR. CHAIRMAN: Don't go so long.

PROF. CHANDRESH P. i
THAKUR: Then I can withdraw.

MR. CHAIRMAN: Okay.

**Estimated demand of steel by the year
2000**

*204. SHRI KAMAL MORARKA:
Will the Minister of STEEL AND
MINES be pleased to state:

(a) what is the estimated demand of
steel by the year 2000;

(b) what is the capacity of the integrated
steel plants and the secondary steel
sector at present;

(c) what is the optimum economic
capacity of the integrated steel plants;

(d) whether after expansion of the
integrated steel plants and expansion of the
existing large plants in the secondary sector,
Government expect a gap between demand
and supply as projected for the year 2000;
and

(e) whether in view of the above,
Government feel the need to allow new steel
plants to come up rather than expanding the
existing ones?

THE MINISTER OF STEEL AND
MINES WITH ADDITIONAL CHARGE
OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(SHRI DINESH GOSWAMI): (a) to
(e) A Statement is laid on the Table of the
House. •

Statement

(a) The VIII Plan Working Group on
Iron & Steel has estimated the total demand
for finished steel for the year 1990-2000 as 31
million tonnes.

(b) The current achievable capacity of
the integrated steel

plants is as under:

(Crude Steel in million tonnes)

Plant	Achievable capacity
Bhilai	4.00
Durgapur	1.15
Rourkela	1.40-
Bokaro .	4.00
IISCO .	0.37
TISCO .	2.40-

The Vizag Steel Plant (capacity of 3
MT per annum) will come on stream in
1992.

The total electric steel making capacity
in the secondary steel sector for which
industrial licences have been issued is 6.36
MTs.

(c) The optimum economic
capacity of integrated steel plants
will vary depending upon a variety
of factors such as location, product-
mix, infrastructure cost etc. It is
unlikely that a conventional in-
tegrated steel plant will be viable
financially if it is of a capacity of
less than 1.50 to 2.00 million tonnes
per annum in our country.

(d) Yes, Sir.

(e) Both expansion and new steel
projects are necessary.

SHRI KAMAL MORARKA:
Sir, the Minister has laid a state
ment on the Table of the House.
The basic thrust of the question
is the gap between demand and
supply of steel. The Minister
himself has said an integrated steel plant at 2
million tonnes capacity would become
viable. Sir, my first question is, has the
Government chalked out a plan to expand
the public sector steel plants to